भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2091

दिनांक 12.03.2025 को उत्तर के लिए

'नेवा' परियोजना

2091. श्री जुगल किशोर:

श्री शंकर लालवानी:

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना के लिए कितना बजट आबंटित किया गया है**;**

(ख) बिहार जैसे राज्यों को उनके कार्यान्वयन प्रयासों में सहायता करने के लिए इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है**;**

(ग) केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार विधान सभा द्वारा किन प्रमुख आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया; और

(घ) बिहार विधान सभा के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान 'नेवा' सॉफ्टवेयर से संबंधित किन विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की गई**?**

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना के लिए कुल 673.94 करोड़ रुपये की लागत आवंटित की गई है ।

(ख) परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार**,** नेवा के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। यह सहायता उन्हें

समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने और उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन के बाद 'डिजिटल सदनों' में परिवर्तित होने में सक्षम बनाती है। इसके अनुरूप, बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद को क्रमशः ₹15,97,00,100/- और ₹8,21,46,550/- की कुल लागत के साथ परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण साझा किया गया है। आज तक, बिहार विधान सभा के लिए पहली किस्त (केंद्रीय हिस्सेदारी का 20%) के रूप में ₹1,91,64,012/- जारी किए जा चुके हैं, जबकि बिहार विधान परिषद को दो किस्तों (केंद्रीय हिस्सेदारी का 20% और 40%) में ₹2,95,72,758/- प्राप्त हुए हैं। यह निधियां नेवा के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आईटी गैजेट्स, हार्डवेयर, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षमता निर्माण और जनशक्ति सेवाओं की खरीद हेतु आबंटित की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार विधान परिषद पहले ही लाइव हो चुकी है और नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सत्रों का सफलतापूर्वक डिजिटल रूप से संचालन कर रही है, जबकि बिहार विधान सभा भी इसका अनुसरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

(ग) और (घ) सॉफ्टवेयर की सामान्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, नेवा परियोजना को एक लचीले ढांचे के साथ डिज़ाइन किया गया है जो अलग-अलग विधानमंडलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए मामूली अनुकूलन और संशोधनों की अनुमति देता है। यह अनुकूलन उनके संबंधित सदन की कार्य पद्धतियों, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं।

*****